(b) what is the GDP of the industries which use agro-based raw material; and

(c) what is the total percentage of population depending on agriculture and what is the percentage of population from agricultural sector living below poverty line?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir. Estimates of GDP by economic activity are available in 'National Accounts Statistics', an annual publication of the Department of Statistics.

(b) For the industries producing food products, beverages, tobacco & related products, cotton textiles, wool and silk textiles, jute and other vegetable fibre textiles using agro-based raw materials as inputs, the estimate of GDP in 1990-91 is Rs. 21,867 crores.

(c) The percentage of cultivators and agricultural labourers to total main workers in the country as per the provisional figures of the 1991 Population Census (which excludes Jammu and Kashmir where the Census has not been held) was 64.9 per cent. Estimates of population below the poverty line by economic activities are not made.

कार्यक्रम की निगरानी करने में जन प्रतिनिधियों का शामिल किया जाना

1723. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न गरीबी हटाओ कार्यक्रमों और 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिला प्राधिकरण/डी०आर०डी०ए० (जोकि कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकरण हैं) क्षेत्र के चुने हुए जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मामलों पर ध्यान देते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु चुने हुए जन प्रतिनिधियों के दृष्टिकोणों को उसमें शामिल करने के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को जारी किए गए मार्ग निर्देशों और प्रस्तावित मार्ग-निर्देशों सहित क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) बीस-सूत्री कार्यक्रम, जिसमें अधिकांश गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शामिल हैं, के कार्यान्वयन का निकटता से प्रबोधन किया जाता है।

(ख) सभी संसद सदस्य तथा जिले के विधान सभा सदस्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी-निकाय के सदस्य हैं तथा उनके द्वारा उठाए गए ध्यान न देने के दृष्टांत संबंधी मामलों को संघ सरकार के ध्यान में लाया नहीं गया है।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को परामर्श देते हुए लिखा था कि संसद सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, विधान परिषद् के सदस्यों, जनता के गैर-सरकारी प्रतिनिधियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर बीस-सूत्री कार्यक्रम के लिये गठित कार्यान्वयन एवं प्रबोधन समितियों में शामिल करें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।